



2026:AHC:10485

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ख संख्या - 114/2026

राजकली

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के वकील : सौरभ सिंह, उत्सव सिंह

विरोधी पक्ष(ओं) के वकील : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. तत्काल एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9क (2) के तहत केस संख्या 313 और 314 (राज्य बनाम लालमणि और अन्य) का शीघ्र निपटारा किए जाने का अनुरोध किया गया है; यह मामला वर्तमान में समेकन अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) के समक्ष विचाराधीन है और निर्धारित अवधि के भीतर इसका निपटारा किया जाना अपेक्षित है।
3. यह निवेदन है कि उपर्युक्त मामला वर्ष 2018 से लंबित है, जबकि मूल आवेदन में विपक्षी पक्ष उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले का शीघ्रता से निपटारा करने हेतु कोई निर्देश जारी किया जाता है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। ऐसा करते समय, न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, जैसा कि रिट याचिका में उल्लेखित है। इसके बजाय, न्यायालय प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देश देता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद—और किसी भी पक्ष को कोई

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनावश्यक स्थगन दिए बिना—उपरोक्त मामले का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार करे। यह निर्णय एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से, शीघ्रतापूर्वक—और अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दस महीने की अवधि के भीतर—किया जाना चाहिए।

6. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

जनवरी 16, 2026

वीआर

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

“Translated, Corrected & Authenticated by SHIKHAR CHANDRA

(ADVOCATE) HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.O.R - A/S1272/2022

UP REGN. No. UP09028/2020”

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”